

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था का 2011-12 में 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 6.9 प्रतिशत तक विकास होने का अनुमान है। 2010-11 में यह वृद्धि 8.4 प्रतिशत थी। 2003-04 से 2010-11 की अवधि में उच्च वृद्धि के सापेक्ष (2008-09 के अपवाद को छोड़कर) 2011-12 की वृद्धि अपेक्षाकृत कम है। इसकी मुख्य वजह लगातार मुद्रास्फीतिकारी दबावों और वैश्विक आर्थिक स्थिति की बिगड़ती स्थिति के चलते कमजोर पड़ती औद्योगिक वृद्धि है। मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने हेतु मौद्रिक नीति में सख्ती विशेष रूप से सकल मांग में कमी लाने का कार्य करती है और 2011-12 में यह स्पष्ट रूप से देखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 2010 से नीतिगत दरों में 375 आधार बिन्दु तक की वृद्धि की। सख्त मौद्रिक नीति का प्रभाव, विशेष रूप से स.घ.उ. की तिमाही वृद्धि दरों में परिलक्षित होता है। वर्तमान राजकोषीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में वृद्धि में क्रमोत्तर रूप से कमी आई। तथापि, विश्व की कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष, भारत में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि सबसे अधिक वृद्धियों में है। कारपोरेट सेक्टर की बढ़ती हुई लागतों और कम होते लाभ की गुंजाइशों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में मंदी आने से सरकारी राजस्व में बजट अनुमान से कम वृद्धि देखने को मिली। दूसरी तरफ, सार्वजनिक व्यय मुख्यतया अधिक सब्सिडी जरूरत के कारण लक्ष्य से अधिक होने का राजकोषीय घाटे के स्तर के लिए निहितार्थ था। वित्तीय बाजारों में आम तौर पर वैश्विक घटनाक्रम का प्रभाव और सख्त होती मौद्रिक नीति का प्रभाव परिलक्षित हुआ। 2011-12 की दूसरी छमाही में विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के परिणामस्वरूप तीव्र पूंजी बहिर्प्रवाह हुआ और इसने विनिमय दर पर दबाव डाला। यह प्रवृत्ति जनवरी 2012 से उलट गई है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप हाल के महीनों में अधिकांश सूचकांकों में मुद्रास्फीति में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी है। इस बात के कुछ संकेत हैं कि आर्थिक जगत में मंदी अपने सबसे निचले स्तर से उबर चुकी है और 2012-13 में क्रमिक बढ़ोतरी आने के संभावना है।

स.घ.उ. वृद्धि

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में उपादान लागत पर 2009-10 और 2010-11 प्रत्येक में 8.4 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने का अनुमान है। यह वृद्धि न केवल विगत हाल की तुलना में बल्कि 2003-04 के बाद वृद्धि की प्रवृत्तियों के संदर्भ में

देखने पर भी कमतर है। 2011-12 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि में कमी मुख्यतया औद्योगिक सेक्टर, जिसमें 2010-11 में 7.2 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, में आई मंदी तथा कृषि क्षेत्र में 2010-11 में प्राप्त 7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि की तुलना में 2.5 प्रतिशत की निम्न वृद्धि के कारण रही है। सेवा क्षेत्र में 2011-12 में अपेक्षतया 9.4 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है जो कमोबेश 2010-11 के स्तर के समान ही है। इस मंदी का कारण घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों को माना जा सकता है। वैश्विक कारकों में, विशेष रूप से, यूरो जोन क्षेत्र में संकट और यूरोप में व्याप्त लगभग मंदी की स्थितियां, कई अन्य औद्योगिक देशों में मंद वृद्धि, कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी आदि शामिल हैं। घरेलू कारकों, अर्थात् मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति की सख्ती के परिणामस्वरूप, निवेश और वृद्धि में, विशेषकर औद्योगिक सेक्टर में कमी आई। वृद्धि को योगदान के संदर्भ में मौजूदा वर्ष में सेवा क्षेत्र में लगभग 79 प्रतिशत की वृद्धि रही, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन और संचार ने 44 प्रतिशत से अधिक का योगदान किया। दूसरी तरफ, स.घ.उ. में समग्र वृद्धि में उद्योग और कृषि क्षेत्रों का योगदान 2011-12 में क्रमशः 16 प्रतिशत और 5 प्रतिशत था।

सीएसओ द्वारा जारी तिमाही आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वर्ष की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में वृद्धि 6.1 प्रतिशत थी। यह वृद्धि 2008-09 की तीसरी तिमाही के बाद से न्यूनतम रही है। कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टरों में वृद्धि 2011-12 की तीसरी तिमाही में क्रमशः 2.7 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि 2010-11 की इसी तिमाही में यह क्रमशः 11.0 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत थी। वर्तमान वर्ष में पहली तीन तिमाहियों में कुल मिलाकर संचयी वृद्धि पिछले वर्ष इसी अवधि में 8.1 प्रतिशत की तुलना में 6.9 प्रतिशत बैठती है। उद्योग और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि 3.6 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत थी, जबकि सेवा क्षेत्र में यह 9.4 प्रतिशत थी।

प्राक्कलन की व्यय पद्धति के संदर्भ में, स्थिर बाजार मूल्यों पर बाजार मूल्यों में 2010-11 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2011-12 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वृद्धि में इस मंदी का कारण तीन प्रमुख घटकों को माना जा सकता है अर्थात् उपभोग व्यय की वृद्धि, सकल नियत पूंजी निर्माण, निर्यात, जिसमें वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तविक अर्थों में क्रमशः 6.0 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत की गिरावट आई। 2010-11 में इन संकेतकों के संबंध में वृद्धि क्रमशः 8.1 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 22.7 प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि में मौजूदा वर्ष

के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। यह नीतिगत दरों में तीव्र वृद्धि के कारण है जिसके परिणामस्वरूप उधारों की लागतों में वृद्धि हुई। सीएसओ द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, चालू बाजार मूल्यों (बचत दर) पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतें 2009-10 में 33.8 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में 32.3 प्रतिशत रह गईं। इस गिरावट का कारण निजी बचतों, मुख्यतया वित्तीय आस्तियों में घरेलू बचतों में कमी और कुछ हद तक कारपोरेट बचतों में कमी रहा है। दूसरी तरफ 2010-11 के दौरान सार्वजनिक बचतों में वृद्धि दर्ज हुई है।

कृषि उत्पादन

कृषि उत्पादन की बहुत अधिक सीमा तक दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा पर निर्भरता बनी हुई है। पूर्व वर्ष में कम वर्षा के बाद लगभग सामान्य वर्षा होने से 2010-11 में खाद्यान्नों के उत्पादन में पुनः वृद्धि हुई। 2011 के दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान, देश दीर्घावधि औसत (एलपीए) की अपेक्षा 1 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई; इसके अतिरिक्त देश के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार कृषि और संबद्ध सेक्टरों में वृद्धि 2010-11 में 7.0 प्रतिशत आंकी गई है और इसके 2011-12 में 2.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। चावल और गेहू की पैदावार में वृद्धि के चलते, खाद्यान्न उत्पादन 2010-11 में 244.78 मिलियन टन के उच्च स्तर की तुलना में 2011-12 में 250.42 मिलियन टन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष में वृद्धि जहां पिछले वर्ष से कम हो सकती है; यह उच्च आधार स्तर की तुलना में प्राप्त की गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2011-12 में चावल का उत्पादन 102.75 मिलियन टन; गेहू का 88.31 मिलियन टन और कपास की 170 कि.ग्रा. की 34.09 मिलियन गांठें होने का अनुमान है। तथापि, वर्तमान वर्ष में दलहनों का उत्पादन 2010-11 के 18.24 मिलियन टन के स्तर से गिरकर 17.28 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 2010-11 में गन्ने का अनुमानित उत्पादन लगभग 342.4 मिलियन टन और 2011-12 में बढ़कर 347.9 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 में तिलहनों का उत्पादन 2010-11 के 324.79 लाख टन के मुकाबले 305.29 लाख टन होने का अनुमान है।

उपर्युक्त अनुमानों से जहां हाल के वर्षों में उत्पादन स्तर में कुछ सुधार दिखाई पड़ता है, वहीं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि योजना लक्ष्यों से कम हुई है। ग्यारहवीं योजना अवधि में भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 3.3 प्रतिशत आंकी गई है। क्षेत्र के कवरेज में स्पष्ट सीमाबद्धता को देखते हुए दीर्घावधि वृद्धि मुख्यतया फसल की उपज पर निर्भर करती है। इसे वृद्धिशील उत्पादकता लाभों और सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार के जरिए हासिल किए जाने का अनुमान है। इसे प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक कृषि में सकल पूंजी

निर्माण का स्तर है। कृषि क्षेत्र के वर्धित मूल्य में वर्ष 2010-11 में सकल पूंजी निर्माण का अनुपात (स्थिर 2004-05 की कीमतों पर) 2004-05 के 13.5 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 20.1 प्रतिशत हो गया। तथापि, अर्थव्यवस्था के समग्र सकल पूंजी निर्माण में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हिस्से में घट-बढ़ वाली प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के संवर्धन का भी प्रयास किया है, हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहा। वर्ष 2010-11 में 3,75,000 करोड़ रुपए की लक्ष्य की तुलना में कृषि को वास्तविक ऋण 4,46,779 करोड़ रुपए आंका गया। 2011-12 में 4,75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल-अक्टूबर 2011-12 की अवधि में यह 2,62,129 करोड़ रुपए रहा।

कीमतें

वर्ष 2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर) में थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से मापी गई समग्र मुद्रास्फीति का औसत 2010-11 की इसी अवधि के दौरान 9.6 प्रतिशत की तुलना में 9.4 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2011-12 की शुरुआत 9.7 प्रतिशत की समग्र मुद्रास्फीति के साथ हुई जिसने दिसम्बर 2011 में गिरकर 7.5 प्रतिशत होने से पहले सितम्बर, 2011 में थोड़े समय के लिए दो अंक का आंकड़ा छुआ था।

मुद्रास्फीति तीन मुख्य घटकों की वजह से लगभग 9 प्रतिशत के उंचे स्तर पर बनी रही। ये इस प्रकार हैं (क) उच्च खाद्य कीमत मुद्रास्फीति जिसकी वजह से अनाज और दालों की कीमत में गिरावट आई और बेहतर उपलब्धता रही परन्तु यह सामान्यतः उच्च स्तर पर बनी रही और यह हमें कुछ झटके भी दे सकती है, विशेषकर फलों और सब्जियों तथा दूध, अंडे, मछली और मांस जैसे प्रोटीन की प्रचुरता वाली वस्तुओं के संबंध में क्योंकि इनकी बढ़ती मांग आपूर्ति से अधिक रही है, (ख) मुद्रास्फीति का फोकस खाद्य-भिन्न विनिर्माण मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो गया क्योंकि खाद्य कीमतों में स्फीतिकारी दबाव विनिर्माताओं को अंतरित हो गया; तथा (ग) खाद्य, औद्योगिक सामग्री और ईंधनों की बढ़ती वैश्विक पण्य कीमतें जिनकी वजह से घरेलू कीमतों पर लागत बढ़ने से बढ़ोतरी हुई।

तथापि, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (भार 24.31 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण रूप से फरवरी, 2010 के 20.2 प्रतिशत से गिरावट हुई और यह दिसम्बर, 2011 में 2.6 प्रतिशत हो गई जिसका मुख्य कारण अनाजों की उपलब्धता में सुधार और फलों और सब्जियों की कीमतों में मौसमी गिरावट रहा। तथापि, दूध अंडे/मांस/मछली, चना और खाद्य तेल खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ाने की वजह रहे।

प्रमुख सूचकांकों के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीतिकारी (सीपीआई) में सामान्यतः समान प्रवृत्ति दिखाई पड़ी और दिसम्बर, 2011 में गिरकर 7 प्रतिशत से नीचे हो गई। सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति अगस्त 2010 से अगस्त 2011 तक एक अंकीय रहने

के पश्चात सितम्बर 2011 में थोड़े समय के लिए 10.1 प्रतिशत का द्विअंकीय आंकड़ा छूने के पश्चात दिसम्बर 2011 में गिरकर 6.5 प्रतिशत हो गई। दिसम्बर 2011 में सभी सीपीआई के लिए खाद्य मुद्रास्फीति और थोक मूल्य सूचकांक लगभग 2 प्रतिशत पर संतुलित रहे।

उद्योग तथा सेवाएं

औद्योगिक विकास में मुख्यतया वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण 2008-09 की तीसरी तिमाही से अवमंदन शुरू हुआ। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की दृष्टि से मापित समग्र औद्योगिक विकास दिसम्बर, 2008 से जून, 2009 तक नकारात्मक रहा। तथापि, समय पर सरकार के हस्तक्षेप और प्रोत्साहन उपाय किए जाने से औद्योगिक विकास में वापसी रही। 2010-11 में समग्र औद्योगिक विकास 2008-09 के 2.5 प्रतिशत और 2009-10 के 5.3 प्रतिशत के मुकाबले सुधर कर 8.2 प्रतिशत हो गया। तथापि, कमजोर आर्थिक वापसी और मंद घरेलू माहौल के परिणामस्वरूप 2011-12 में संतुलित विकास कायम रहा है। 2011-12 के प्रथम नौ माह (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान आईआईपी में विगत वर्ष की इसी अवधि के 8.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्र, जिसका आईआईपी में 75.5 प्रतिशत का भार है, में भी अप्रैल-दिसम्बर, 2011 में अप्रैल-दिसम्बर 2010 की 9.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि का महत्वपूर्ण संतुलन देखा गया। खनन क्षेत्र में उत्पादन विगत वर्ष की इसी अवधि के 6.9 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अप्रैल-दिसम्बर, 2011 में घटकर 2.7 प्रतिशत हो गया। उत्पादन में इस कमी की वजह कोयला और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि रही है। तथापि विद्युत क्षेत्र में विगत वर्ष की इसी अवधि की 4.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अप्रैल-दिसम्बर, 2011 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उछाल रहा है। स.घ.उ. में योगदान की दृष्टि से सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रणी क्षेत्र है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2011-12 में सेवा क्षेत्र के 2010-11 में हासिल 9.3 प्रतिशत वृद्धि के अतिरिक्त 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर की प्रत्याशा है।

वैदेशिक क्षेत्र

भारत की निर्यात एवं आयात वृद्धि जिसने 2010-11 में गति पकड़ी, 2011-12 के दौरान सुदृढ़ बनी रही। 2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 217.7 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात के साथ 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) के 173 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर के मुकाबले 25.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान आयात का मूल्य 350.9 बिलियन अमरीकी डालर था जो 2010-11 की इसी अवधि के 269.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 30.4 प्रतिशत अधिक था। सोना और चांदी की कीमतों में वृद्धि के साथ बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों

का आयात बिल में काफी योगदान रहा। कुल आयात में से पीओएल का आयात अप्रैल-दिसम्बर, 2011 में 105.6 बिलियन अमरीकी डालर (कुल आयात का 30.1 प्रतिशत) रहा जो 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) के 75.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 40.4 प्रतिशत अधिक था। 2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान गैर-पीओएल आयात की राशि 245.3 बिलियन अमरीकी डालर रही जो 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) के 194 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 26.5 प्रतिशत अधिक था। परिणामस्वरूप, 2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर) का व्यापार घाटा बढ़कर 133.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) के 96.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 38.5 प्रतिशत अधिक था।

जहां पण्य व्यापार आंकड़ा अप्रैल-दिसम्बर 2011 की अवधि के लिए उपलब्ध है, वहीं भुगतान संतुलन संबंधी अधिकांश जानकारी 2011-12 की पहली छमाही अर्थात् सितम्बर 2011 तक की ही उपलब्ध है। भारत में सामान्यतः नान-फैक्टर सेवाओं के निर्यात के सुदृढ़ स्तर से माल एवं सेवा संतुलन में घाटे का स्तर कम होता है। 2011-12 की पहली छमाही में माल एवं सेवाओं का घाटा 54.7 बिलियन अमरीकी डालर रहा। 2011-12 की पहली छमाही में 30.9 बिलियन अमरीकी डालर में निजी अंतरणों (प्रेषण) के फलस्वरूप 52.9 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अदृश्य अधिशेष रहा। 2011-12 की पहली छमाही में चालू खाता घाटा 2010-11 की इसी अवधि के 29.6 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले बढ़कर 32.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जिसकी मुख्य वजह उच्च व्यापार घाटा रही।

2011-12 की पहली छमाही में मौजूदा लेखा घाटे के वित्त पोषण हेतु पूंजी अन्तर्प्रवाह के स्तर पर्याप्त थे। निवल अर्थ में, पूंजी अन्तर्प्रवाह में 2010-11 की पहली छमाही में 39.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़ोतरी होकर यह 2011-12 की पहली छमाही में 41.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2011-12 की पहली छमाही में 12.3 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर पर था जबकि 2010-11 की इसी अवधि में यह 7 बिलियन अमरीकी डालर था। तथापि, निवल पोर्टफोलियो निवेश में पर्याप्त गिरावट देखी गयी और यह उक्त उसी अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से घटकर 23.8 बिलियन अमरीकी डालर से 1.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। ऐसा एफआईआई में भारी गिरावट की वजह से हुआ जो 22.3 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2011-12 में 0.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। ईसीबी तथा बैंकिंग पूंजी सहित अन्य पूंजी प्रवाह में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई जिसने पर्याप्त पोर्टफोलियो प्रवाहों की अपेक्षाकृत कम क्षतिपूर्ति की। 2011-12 की पहली छमाही के दौरान प्रारक्षित निधियों से सम्बद्ध निवल वृद्धि (बीओपी आधार पर प्रारक्षित परिवर्तन) 5.7 बिलियन अमरीकी डालर के निम्नस्तर पर थी जबकि पिछले वर्ष की पहली छमाही में यह 7 बिलियन अमरीकी डालर था। ऐसा मुख्यतः सीएडी को व्यापक रूप देने की वजह से हुआ।

रुपए ने 2011-12 के कुछ भागों हेतु घटती प्रवृत्ति को दिखाया रुपए की मासिक औसत विनिमय दर प्रति अमरीकी डालर 44.97 रुपए से 51.34 रुपए के बीच रही। बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर रुपए में 16.2 प्रतिशत तक का मूल्य ह्रास देखा गया जो 31 मार्च, 2011 को 44.67 प्रति अमरीकी डालर से 30 दिसम्बर, 2011 को 53.26 प्रति अमरीकी डालर हो गया। रुपया 27 जुलाई, 2011 को 43.94 के शीर्ष पर पहुंच गया और 15 दिसम्बर, 2011 को यह 54.23 प्रति अमरीकी डालर के सर्वाधिक निम्न स्तर पर था जो 19.0 प्रतिशत के मूल्य ह्रास को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार मार्च, 2011 तथा दिसम्बर, 2011 के बीच रुपए की मासिक औसत विनिमय दर पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में 11.5 प्रतिशत, यूरो की तुलना में 9.1 प्रतिशत और जापानी येन की तुलना में 18.7 प्रतिशत तक मूल्य ह्रास हुआ। 2011-12 में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में 6.7 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ोतरी हुई जो मार्च 2011 के अन्त में 304.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर सितम्बर 2011 के अन्त में 311.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गयी। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां दिसम्बर 2011 के अन्त में 296.7 बिलियन अमरीकी डालर थी। भारत का विदेशी ऋण स्टॉक सितम्बर 2011 के अन्त में 326.6 बिलियन अमरीकी डालर था जिसने मार्च 2011 के अन्त में 306.4 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानों की तुलना में 20.2 बिलियन अमरीकी डालर (6.6 प्रतिशत) की बढ़ोतरी दर्ज की। यह बढ़ोतरी मुख्यतः उच्च वाणिज्यिक उधारों तथा अल्पावधिक ऋण के कारण थी।

मुद्रा, बैंकिंग तथा पूंजी बाजार

मुद्रा स्फीति पर काबू पाना 2011-12 के दौरान मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 और जनवरी 2012 के बीच संचयी रूप से 375 आधार बिन्दु (बीपीएस) तक रीपो दर में 13 बार बढ़ोतरी की। खाद्य मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में आपूर्ति कारक तथा उन्नत देशों में व्याप्त अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य से मौद्रिक नीति का कार्य विशेष रूप से चुनौती पूर्ण था। ठोस मौद्रिक नीति तथा विशेष रूप से बराबर रीपो दर में बढ़ोतरी से विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि, दिसम्बर 2011 से जनवरी 2012 तक की अवधि के दौरान इस स्थिति में बदलाव देखा गया जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति तीसरी तिमाही-समीक्षा में रीपो तथा रिवर्स रीपो दर को क्रमशः 8.5 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तन रखा। तथापि, नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) को 6.0 से घटाकर 5.5 प्रतिशत और बाद में 4.75 प्रतिशत तक कर दिया ताकि नकदी स्थिति की सुगमता बनी रहे। मौद्रिक नीति की प्रचालन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। भारांश औसत एक दिवसीय मांग मुद्रा दर को प्रचालन लक्ष्य बनाया गया है और विनिर्दिष्ट रीपो दर को ही स्वतंत्र रूप से परिवर्तित नीति दर माना गया। एक नई औसत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) को तैयार किया गया है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को अपने विवेक पर अपनी सम्बद्ध निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के रीपो दर <http://indiabudget.nic.in>

से ऊपर 100 आधार बिन्दुओं पर 1 प्रतिशत तक एक दिवसीय उधार लेने की अनुमति दी गयी है। संशोधित कोरिडोर को 200 आधार बिन्दुओं की निश्चित विस्तार के साथ परिभाषित किया गया है और रीपो रेट को कोरिडोर के मध्य में रखा गया है तथा रिवर्स रीपो रेट को इससे नीचे 100 आधार बिन्दुओं पर रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी, 2012 को एक बारगी तकनीकी समायोजन के रूप में पुनः बैंक दर को 9.5 प्रतिशत के एमएसएफ की बैंक दर से संयोजित किया है।

2011-12 के दौरान, प्रारक्षित मुद्रा में विकास दर (एम₀) 1.9 प्रतिशत (10 फरवरी, 2012 की स्थिति अनुसार) रही है जबकि स्थूल मुद्रा (एम₁) विकास दर 10.2 प्रतिशत (27 जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार) रही है। वर्षानुवर्ष खाद्य भिन्न ऋण में दिसम्बर 2011 के अन्त में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नकदी दशाएं सामान्यतः 2011-12 के दौरान घाटे में रहीं।

ब्याज दरों में उत्तरोत्तर अविनियमन को ध्यान में रखते हुए, बचत बैंक लेखा ब्याज दरें 25 अक्टूबर, 2011 से अविनियमित की गयी जिसमें बैंकों को 1 लाख रुपए तक की जमा राशियों की बचत लेखों हेतु समरूप ब्याज दरों को रखना होगा जबकि विभेदक ब्याज दरें 1 लाख रुपए से अधिक की बचत जमा राशियों हेतु निर्धारित की जा सकती हैं। इससे बचत लेखों की आकर्षकता बढ़ाने और बदलती बाजार दशाओं के अनुरूप बचत जमा दरों से अर्थव्यवस्था में मितव्ययी व्यवहार को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

देश में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अंतर्प्रवाहों में कमी आने से भारतीय बाजारों में गिरावट आई और इसकी वजह से रुपए का तीव्र अवमूल्यन हुआ, यद्यपि अधिकांश अवमूल्यन यूरोप में मंदी और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के चलते, विदेशी निवेशकों द्वारा 'सुरक्षित पलायन' के कारण था। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी ने बाजार माहौल को भी प्रभावित किया है। पात्र विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को जनवरी, 2012 में भारतीय इक्विटी बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने की अनुमति दी गई। यह निवेशकों की श्रेणी का विस्तार करने, अधिक विदेशी निधियों को आकर्षित करने, बाजार अस्थिरता को कम करने और भारतीय पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने के लिए किया गया। इससे पूर्व केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप-खातों और अनिवासी भारतीयों को ही भारतीय इक्विटी बाजारों में सीधे निवेश करने की अनुमति थी।

केन्द्र सरकार की वित्त व्यवस्था

2010-11 में पर्याप्त राजकोषीय समेकन हुआ। राजकोषीय घाटा 2009-10 में स.घ.उ. के 6.4 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गया और यह कर और कर-भिन्न राजस्व में बजट अनुमान से अधिक वृद्धि तथा उच्चतर अभिहीत स.घ.उ. के बलबूते प्राप्त किया जा सका। 2011-12 का बजट प्रस्तुत करते समय वृहत आर्थिक संभावनाएं सकारात्मक थी और 2011-12 के बजट

में राजकोषीय लक्ष्यों को उपयुक्त रूप से निर्धारित करके राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 4.6 प्रतिशत तक नीचे लाने का अनुमान किया गया था। तथापि, बाद के आर्थिक घटनाक्रम ने कुछ हद तक दूसरा मोड़ ले लिया। अन्तरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई। यूरोजोन में व्याप्त आर्थिक संकट तथा मध्य पूर्व एशिया में राजनीतिक संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई रूपों में प्रभाव डाला। निरन्तर उच्च मुद्रास्फीति जिसका नतीजा सख्त मौद्रिक नीति अपनाने के रूप में सामने आया, के परिणामस्वरूप उत्पादन और मांग में न्यूनतर वृद्धि हुई और इसका प्रभाव राजस्व पर पड़ा। व्यय के बजट अनुमान की अपेक्षा अधिक होने से, राजकोषीय परिणाम के संदर्भ में बजटीय लक्ष्यों की पूर्ति में 2011-12 में जाना अपरिहार्य है। लेखा महानियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दिसम्बर, 2011 तक ब.अ. स्तरों के क्रमशः 93.1 प्रतिशत और 92.3 प्रतिशत तक पहुंच गया था। पहले नौ महीनों में, सकल कर राजस्व 17.6 प्रतिशत के ब.अ. लक्ष्य की तुलना में 12.2 प्रतिशत तक बढ़ गया है। प्रमुख करों में, निगम करों में बजट अनुमान 2011-12 द्वारा परिकल्पित 20.5 प्रतिशत की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बजट अनुमान 2011-12 द्वारा परिकल्पित 18.7 प्रतिशत की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि ने सरकार के वित्तपोषण पर अपरिहार्य प्रभाव डाला। सेवा कर में 37 प्रतिशत, सीमा शुल्क में 15 प्रतिशत और वैयक्तिक आयकर में 16 प्रतिशत की वृद्धि या तो 2011-12 के बजट अनुमानों के समकक्ष है अथवा उससे अधिक है। 2011-12 के पहले नौ महीनों में कुल व्यय में वृद्धि 13.9 प्रतिशत थी, जिसमें आयोजना-भिन्न व्यय में 15.4 प्रतिशत वृद्धि और आयोजना व्यय में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। नौ महीनों के दौरान व्यय में बढ़ोतरी और राजस्व में आनुपातिक से कम वृद्धि होने के परिणामस्वरूप पहले नौ महीनों में घाटे का अनुपात काफी अधिक

है। इसके परिणामस्वरूप संशोधित अनुमानों में 2011-12 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 5.9 प्रतिशत और राजस्व घाटा स.घ.उ. 4.4 प्रतिशत आंका गया है।

सम्भावनाएं

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि जैसे कतिपय बहिर्जात झटकों के साथ-साथ यूरोप में वित्तीय संकट का परिणाम 2011 के दौरान तीव्र वैश्विक आर्थिक मंदी के रूप में सामने आया। घरेलू स्तर पर, वर्ष के अधिकांश समय मुद्रास्फीति 9 प्रतिशत बनी रही। मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति में सख्ती अपनानी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसकी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 2011-12 दौरान 6.9 प्रतिशत तक गिर जाने का अनुमान है। ऐसे संकेत हैं कि 2012-13 में वृद्धि दर मौजूदा वर्ष की सम्भावित दर से अधिक होगी। हाल के महीनों में मुद्रास्फीति में कमी का रुझान दिखाई दे रहा है। मुद्रास्फीति में और कमी आने से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सख्त मौद्रिक उपायों को उलटा जा सकता है जिससे निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे ही राजकोषीय समेकन पटरी पर लौटेगा, बचत और निवेश में भी वृद्धि होनी चाहिए। इन कारणों, तथा इस तथ्य कि मंदी के बावजूद, 2010-11 में भारत की निवेश दर 35.1 प्रतिशत रही है, के परिणामस्वरूप 2012-13 में विकास में सुदृढ़ता आनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, 2012-13 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6(+/-0.25) प्रतिशत होने की आशा करनी चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि ये पूर्वानुमान सामान्य वर्षा, पेट्रोलियम उत्पादों के पर्याप्त रूप से स्थिर मूल्यों आदि जैसी स्थितियों पर निर्भर हैं।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
वास्तविक क्षेत्र					
1.	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)*				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	7157 ^{त्व.अ.}	8280 ^{अ.अ.}	17.5 ^{त्व.अ.}	15.7 ^{अ.अ.}
	(ख) 2004-2005 के मूल्यों पर	4886 ^{त्व.अ.}	5222 ^{अ.अ.}	8.4 ^{त्व.अ.}	6.9 ^{अ.अ.}
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2004-05=100)	161.0	166.8	8.3	3.6
3.	थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2004-05=100) @	141.6	154.9	9.6	9.4
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:औद्योगिक कामगार (2001=100) @	177.7	193.3	11.0	8.8
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (हजार करोड़ रुपए)\$	6202	7199	17.3	16.0
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात**				
	(क) करोड़ रुपए	1228074	1651240	23.8	34.5
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	269175	350936	29.8	30.4
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात **				
	(क) करोड़ रुपए	789069	1024707	29.6	29.9
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	172965	217664	36.0	25.8
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर) **	-96210	-133272	20.1	38.5
9.	विदेशी मुद्रा भंडार				
	(क) बिलियन रुपए में	13324	15804	0.7	18.6
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर में	297334	296688	4.9	-0.2
10.	चालू लेखा शेष (मिलियन अमरीकी डालर में) (अप्रैल-सितंबर)	-29599	-32842
सरकारी वित्त साधन #					
1.	राजस्व प्राप्तियां	584268	498491	50.1	-14.7
2.	कर राजस्व (निवल)	391148	420414	27.2	7.5
3.	कर-भिन्न राजस्व	193120	78077	136.4	-59.6
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	202584	397870	-36.3	96.4
5.	ऋणों की वसूली	8591	14115	115.7	64.3
6.	अन्य प्राप्तियां	22744	2743	428.2	-87.9
7.	उधार और अन्य देनदारियां	171249	381012	-44.8	122.5
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	786852	896361	11.2	13.9
9.	आयोजना-भिन्न व्यय	536898	619457	7.9	15.4
10.	राजस्व खाता	487692	550692	5.8	12.9
<i>जिसमें:</i>					
11.	ब्याज भुगतान	146304	179429	12.5	22.6
12.	पूंजी खाता	49206	68765	35.1	39.7
13.	आयोजना व्यय	249954	276904	18.9	10.8
14.	राजस्व खाता	212885	233903	18.6	9.9
15.	पूंजी खाता	37069	43001	21.1	16.0
16.	कुल व्यय (9+13)	786852	896361	11.2	13.9
17.	राजस्व व्यय (10+14)	700577	784595	9.4	12.0
18.	पूंजी व्यय (12+15)	86275	111766	28.7	29.5
19.	राजस्व घाटा (17-1)	116309	286104	-53.7	146.0
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	171249	381012	-44.8	122.5
21.	प्रारम्भिक घाटा (20-11)	24945	201583	-86.1	708.1

त्व.अ. त्वरित अनुमान;

अ.अ. अग्रिम अनुमान

* पूर्ण वर्ष से संबंधित

@ अप्रैल से दिसम्बर की औसत

\$ एम₃ संबंधी आंकड़े वर्ष 2010-11 के लिए 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार और 2011-12 के लिए 30 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं।

** सीमाशुल्क आधार पर; चालू वर्ष हेतु तुलना संशोधित आधार की तुलना में अनन्तिम आधार पर।

लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े